गुरु रविदास ने समरसता के संदेश से समाज को एक सूत्र में पिरोया- भजनलाल

गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाये गए पावन रज कलश की रथयात्रा सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना

जयपुर, 5 अगस्त। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष में आयोजित "समरसता संकल्प अभियान" का प्रदेश स्तरीय शुभारंभ बुधवार को जयपुर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, समरसता संकल्प अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, अभियान के प्रदेश संयोजक भूपेन्द्र सैनी सहित, संत-महात्माओं और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गुरु रविदास की

■ **समरसता संकल्प अभियान के तहत यह रथयात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन प्रवास करेगी तथा स्थानीय स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष में आयोजित "समरसता संकल्प अभियान" के प्रदेश स्तरीय समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा मौजूद थे।

जन्मस्थली से लाए गए पावन रज कलश राजस्थान की सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किये। रज कलश ले जा रहे रथ प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा, मंडल और गांव-ढाणी तक पहुंचकर सामाजिक समरसता, समानता और संत रविदास के विचारों का संदेश देंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत की संत परंपरा ने सदैव राष्ट्र और समाज को दिशा देने का कार्य किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास ने समानता, भाईचारे, मानवता और सामाजिक समरसता का संदेश देकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का संत रविदास से ऐतिहासिक संबंध रहा है और चित्तौड़गढ़ में विकसित किया गया पैनोरमा नई पीढ़ी को उनके विचारों से जोड़ने का माध्यम बनेगा।

अभियान के राष्ट्रीय संयोजक लाल सिंह आर्य ने कहा कि संत रविदास का प्रसिद्ध संदेश "जाति-पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई" सामाजिक समरसता का मूल मंत्र है।"

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने लगभग 650 वर्ष पूर्व समाज को समरसता, समानता और कर्मप्रधान जीवन का संदेश दिया था।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता, प्रेम और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि संत रविदास के आदर्श आज भी समाज को समानता, सद्भाव और आत्मीयता के सूत्र में बांधने की प्रेरणा देते हैं।

अभियान के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सैनी ने स्वागत उद्बोधन में बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रथ एक दिन प्रवास करेगा और स्थानीय स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कानपुर- लखनऊ एक्सप्रेसवे धंसने पर निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्यवाही

नई दिल्ली, 05 अगस्त। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने निर्माण कंपनी, स्वतंत्र इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। एनएचएआई ने निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन-परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही एक्सप्रेसवे पर फिलहाल टोल वसूली भी रोक दी गई है।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 26 जुलाई को किलोमीटर 64 के पास करीब 300 मीटर हिस्से में सड़क धंसने (स्लिपेज) की घटना सामने आई थी। इसके बाद एनएचएआई ने तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराया और प्रभावित हिस्से की व्यापक तकनीकी जांच के आदेश दिए। एनएचएआई ने पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ सुरक्षा राशि का दो प्रतिशत जुर्माना लगाने, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तीन वर्ष तक डिबारमेंट की कार्रवाई करने तथा कंपनी की रेटिंग घटाने का प्रस्ताव रखा है।

सुप्रीम कोर्ट की समिति 7 से 10 अगस्त अरावली जिलों में फील्ड विज़िट करेगी

समिति 7 को सरिस्का, 8 को अजमेर व 10 को उदयपुर में अधिकारियों, ग्रामीणों, किसानों से जनसंवाद करेगी

■ **राज्य सरकार ने खान विभाग के निदेशक महावीर प्रसाद मीणा तथा अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक श्रीमती टी जे कविता को समिति की फील्ड विज़िट के लिए नोडल अधिकारी बनाया है।**

जयपुर, 5 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली को परिभाषित करने के संबंध में महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा राजस्थान के चयनित अरावली जिलों का 7 से 10 अगस्त तक फील्ड दौरा किया जाएगा।

उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा फील्ड विज़िट का मुख्य उद्देष्य क्षेत्र की पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक, हाइड्रोलॉजिकल, जैव विविधता, खनन भूमि उपयोग और सामाजिक आर्थिक बिन्दुओं का अध्ययन करना है। समिति की फील्ड विज़ट के लिए राज्य सरकार द्वारा खान विभाग के निदेशक महावीर प्रसाद मीणा को नोडल अधिकारी और बीएस सोढ़ा अतिरिक्त निदेशक खान को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार से वन विभाग की अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक टीजे कविथा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा 7 अगस्त को कोटपुतली, नीम का थाना, सरिस्का क्षेत्र का फील्ड विज़िट किया जाएगा। आठ अगस्त को जयपुर के साथ ही किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र का फील्ड विज़िट किया जाएगा। इसी तरह से 9 अगस्त को राजसमंद और उदयपुर क्षेत्र का फील्ड विज़िट किया जाएगा।

टीम के सदस्य इन क्षेत्रों में जिला कलक्टरों, खान-वन व संबंधित विभागों के अधिकारियों, खान पट्टाधारकों, पर्यावरणविदों, स्वयंसेवी संस्थाओं, खनन एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, खनन श्रमिकों, विशेषज्ञों, स्थानीय ग्रामीणों व किसानों से संवाद करेंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइन्स अपर्णा अरोरा ने बुधवार को सचिवालय में उच्चस्तरीय समिति के दौरे के संदर्भ में खान एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की।

कैबिनेट सचिव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी को उनके मूल कैडर में एक विस्तारित "कूलिंग ऑफ" अवधि के लिए वापस भेजने की भी मंजूरी दी है। सोमनाथन, जो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और तमिलनाडु कैडर से हैं, पहले वित्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। वे 30 अगस्त, 2024 से कैबिनेट सचिव के पद पर हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। इस ब्यूरोक्रेट ने वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह के निदेशक के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने युवा पेशेवर कार्यक्रम के तहत शुरुआत की थी।

गोविंद मोहन 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और सिक्किम कैडर से हैं, जो 23 अगस्त, 2024 से गृह सचिव के रूप में कार्यरत हैं। द्विवेदी 1997 बैच के एजीएमयूटी कैडर के अधिकारी हैं। उनको पिछले वर्ष नियुक्ति समिति ने नवंबर, 2026 तक विस्तार दिया था।

बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनीत

पटना, 05 अगस्त। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेन्द्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद की सदस्यता मिल गई है। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। नवंबर 2025 में दीपक प्रकाश पहली बार राज्य की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री बने थे। अप्रैल 2026 में जब बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री सहित नई सरकार का गठन हुआ तो दीपक प्रकाश दोबारा मंत्री बनाए गए।

प्रधानमंत्री ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नियमित रूप से उपस्थित रहने और सक्रिय भागीदारी निभाने की सलाह दी। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में संयम, शिष्टाचार और गरिमापूर्ण आचरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने सांसदों से सोशल मीडिया और तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी तथा सावधानी के साथ करने को कहा।

बैठक के बाद कई सांसदों ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री से मुलाकात के अनुभव साझा किए।

भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य नितिन नबीन ने अपने एक्स हैंडल पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सभी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं।

केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिजिजू से कहा है कि वे राहुल गांधी से जितनी बार संभव हो, मुलाकात करें और उन्हें सरकार के समर्थन के लिए तैयार करने की कोशिश करें। आज राहुल गांधी 10 जनपथ के बाहर कुछ और छात्रों को मीडिया से बातचीत के लिए लेकर आए, ताकि वे बता सकें कि पुलिस ने उनके साथ किस तरह मारपीट की और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान क्या हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि यदि छात्र बिना किसी डर के अपनी बात कह सकते हैं, तो फिर भारत के गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर देश को यह क्यों नहीं बताते कि उस दिन क्या हुआ था? तथा क्या छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठीचार्ज करने और आंसू गैस छोड़ने का आदेश उन्होंने दिया था, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हुए? अब यह सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की देश और संसद के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं? दूसरा सवाल यह है कि जब संसद का नियमित सत्र ही ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो विशेष सत्र कैसे चलेगा? विपक्ष ऐसे विशेष सत्र को चलने कैसे देगा? विपक्ष का आरोप है कि सरकार मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और अपना पूरा ध्यान परिसीमन के मुद्दे पर लगा रही है। यह एक संवैधानिक संशोधन है, जिसके लिए विधिवत मतदान आवश्यक है। इसे शोर-शराबे और हंगामे के बीच पारित नहीं किया जा सकता।

परिसीमन और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कराना चाहती है। लेकिन सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने सरकार के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया।

सूत्रों ने बताया कि विपक्ष के नेता ने किरेन रिजिजू से कहा कि जब तक राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले पर चर्चा नहीं होती और 20 जुलाई को राजधानी में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान नहीं देते, तब तक सदन में कोई कामकाज नहीं हो सकता।

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद, किरेन रिजिजू ने संसद के गतिरोध पर चर्चा करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की।

विपक्ष के सख्त रुख के कारण सरकार की इस सत्र में परिसीमन विधेयक पारित कराने की योजना पर रोक लग गई है। सूत्रों के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से नेताओं के पाला बदलने के कारण सदन में बढ़ी संख्या के आधार पर सरकार को उम्मीद थी कि वह पिछले सत्र में पारित न हो सके इस विवादित विधेयक को इस बार पास करा लेगी।

विपक्ष, छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर लगातार अमित शाह को निशाना बना रहा है और उनसे सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि किसी प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग का फैसला गृह मंत्री नहीं, बल्कि संबंधित मजिस्ट्रेट करता है।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला विपक्ष राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे पर भी केन्द्र सरकार पर हमला बोल रहा है और इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहा है।

पिछले कई दिनों से विपक्षी सांसद संसद परिसर के भीतर प्रतीकात्मक चंदा पेटियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को निशाना बना रहे हैं।

20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के बाद से लोकसभा में एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका है। हंगामे के बीच बिना चर्चा के पांच विधेयक पारित किए जा चुके हैं।

बुधवार को भी लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी जारी रखी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदस्यों से अपनी-अपनी सीटों पर लौटने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से कहा, "सदन के भीतर हो या बाहर, नारेबाजी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। तख्तियां दिखाकर और नारे लगाकर आप सदन की गरिमा को कम कर रहे हैं।" बिड़ला ने कहा कि कई सांसद उनसे मिले और बताया कि उनके महत्वपूर्ण प्रश्न सूचीबद्ध हैं, लेकिन मानसून सत्र में विपक्ष द्वारा किए जा रहे लगातार हंगामे के कारण सदन प्रश्नकाल नहीं चला पा रहा है।

मैटा ने वीडियो हटाने के मामले में प्रधानमंत्री से माफी मांगी

नई दिल्ली, 05 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वीडियो हटाए जाने और बाल यौन शोषण एवं दुरुपयोग सामग्री (सीएसएएम) से जुड़े कथित विज्ञापनों के मामले में मेटा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सरकार से माफी मांगी है। सूत्रों के अनुसार, मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क ज़ुकरबर्ग ने सीएसएएम, डीपफेक सामग्री और मंच के संचालन में हुई त्रुटियों पर खेद व्यक्त किया है।

■ **मार्क ज़ुकरबर्ग ने सीएसएएम, डीपफेक सामग्री और मंच संचालन में त्रुटियों पर खेद व्यक्त किया।**

सूत्रों ने बताया कि मेटा ने स्वीकार किया कि कुछ खास तरह की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए काफी पैसा दिया गया था। वहीं, सरकार ने कंपनी को स्पष्ट किया है कि अगर मेटा तय करेगा कि कौन-सा कंटेंट किसे दिखाया जाएगा, तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत केवल 'मध्यस्थ' (इंटरमीडियरी) के तौर पर मिलने वाला संरक्षण समाप्त हो जाएगा।

रिज़र्व बैंक ने नई क्रेडिट पॉलिसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की स्थिति सामान्य हो जाने पर ईंधन की महंगाई काफी कम हो जानी चाहिए। इसलिए केवल अस्थायी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाना अर्थव्यवस्था की विकास दर को नुकसान पहुंचा सकता है।

जहां तक खाद्य पदार्थों की कीमतों का सवाल है, इनमें मौसमी उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए महंगाई के ट्रेंड में भी बदलाव आना चाहिए। आम तौर पर गर्मियों के महीनों और अक्टूबर के आखिर में नई फसल आने तक खाद्य पदार्थों के दाम ऊंचे रहते हैं। इसके बाद बाजार में नई उपज आने से कीमतों में नरमी आने लगती है।

इस माहौल को देखते हुए, आरबीआई ने मॉनिटरी पॉलिसी अपेक्षाकृत अधिक उदार रखते हुए इकॉनमी की ग्रोथ को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ग्रोथ और महंगाई के बीच तालमेल के बैंक के विश्लेषण के अनुसार, फिलहाल महंगाई को रोकने के लिए आपातकालीन सख्ती की जरूरत नहीं है, बल्कि विकास को समर्थन देना अधिक उचित है। यह नीति नियंत्रण की चेतावनी के बजाय, विकास को लेकर अधिक आशावादी नजरिया दिखाती है, क्योंकि रिज़र्व बैंक को भरोसा है कि घरेलू मांग से ग्रोथ जारी रहेगी।

रिज़र्व बैंक का कहना है कि उसकी नीति पूरी तरह आंकड़ों पर आधारित है। यानी, जैसे-जैसे नए आर्थिक आंकड़े सामने आएंगे, उसी के अनुसार मॉनिटरी पॉलिसी में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। वैसे तो लगभग सभी केन्द्रीय बैंक ऐसा दावा करते हैं और आरबीआई भी इसी सिद्धांत पर काम कर रहा है।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा अपनी नीति घोषणा में दिए गए आंकड़ों को देखें तो लगता है कि मौजूदा नीति का मुख्य उद्देश्य कीमतों में स्थिरता बनाए रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को जारी रखना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की आम तौर पर निराशाजनक स्थिति के बीच यह एक अच्छी और उम्मीद जगाने वाली नीति मानी जा सकती है।

आरबीआई ने कहा, "लगातार बनी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, घरेलू आर्थिक गतिविधियों ने मजबूती दिखाई है, जैसा कि पहली तिमाही के हाई फ्रीक्वैंसी इंडिकेटर्स से पता चलता है।"

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा बताए गए प्रमुख आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं-

प्राइवेट खपत में अपनी मर्जी से किये जाने वाले खर्च (डिस्क्रीशनरी स्पैंडिंग) की वजह से मजबूती बनी रही, जबकि सरकार द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्माण कार्यों पर मजबूत खर्च के कारण निवेश गतिविधियां भी स्थिर रहीं।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री 14.5 प्रतिशत बढ़ी। इसी अवधि में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 15.1 प्रतिशत और ट्रैक्टरों की बिक्री 21.4 प्रतिशत बढ़ी।

दूसरी ओर इसी दौरान, यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में 21.0 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन इण्डैक्स (आईआईपी) के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री में क्रमशः 21.0 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत की मजबूत रफ्तार से बढ़ोतरी हुई।

पहली तिमाही में इस्पात की खपत 8.3 प्रतिशत बढ़ी, जबकि सीमेंट उत्पादन में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में बंदरगाहों पर माल ढुलाई 6.1 प्रतिशत बढ़ी।

पहली तिमाही के शुरुआती कॉरपोरेट नतीजे बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसकी पुष्टि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) से भी होती है, जो विस्तार का संकेत देता है। मजबूत घरेलू मांग के कारण सर्विस सैक्टर की गतिविधियां भी तेज बनी रहीं।

1 अगस्त 2026 तक 413 लिस्टेड प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के नतीजों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में नैट सेल्स में 21.9 प्रतिशत और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 15.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर के 23 उद्योग समूहों में से 16 ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में पहली तिमाही में पॉज़िटिव ग्रोथ दर्ज की।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 54.6 के साथ एक्स्पैंशन ज़ोन (चौथी तिमाही में 55.4) में बना रहा।

पहली तिमाही में जीएसटी ई-वे बिलों की संख्या 12.4 प्रतिशत बढ़ी, जबकि टोल संग्रह (वाहनों की संख्या के आधार पर) में 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह 8.6 प्रतिशत बढ़ा। इसी अवधि में घरेलू एयर कार्गो में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पंजाब भाजपा में नई नियुक्तियों ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्राथमिकता दी जा रही है जो हाल के वर्षों में अन्य दलों से भाजपा में आये हैं, जबकि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है।

विडंबना यह है कि इस बार कई दलबदलू नेता भी संतुष्ट नहीं हैं। गत 3 अगस्त की संगठनात्मक कवायद का उद्देश्य कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और आम आदमी पार्टी (आप) से आए नेताओं को समायोजित करना था। पार्टी के 12 उपाध्यक्षों में से 6 नेता इन्हीं दलों से आए हैं, लेकिन संतुलन साधने की यह कोशिश किसी भी गुट को संतुष्ट नहीं कर सकी।

सबसे अधिक आपत्ति पार्टी के पाँच महत्वपूर्ण महासचिवों की नियुक्ति को लेकर है। इनमें से तीन-अनिल सरीन, राजेश धीमन और परमिंदर बराड़ (हालांकि उनका नाम मोहाली से दर्शाया गया है, लेकिन उनका राजनीतिक कार्यक्षेत्र मुख्यतः लुधियाना है), लुधियाना से जुड़े हैं। अन्य दो महासचिव जीवन गर्ग (संगरूर) और राकेश बाघा (जालंधर) हैं। आलोचकों का कहना है कि अमृतसर, गुरदासपुर और होशियारपुर जैसे तीन महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्रों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जबकि भाजपा पिछले लगभग 30 वर्षों से इन क्षेत्रों में चुनाव लड़ती रही है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कई नेता भी निजी तौर पर मानते हैं कि उन्हें उनके राजनीतिक प्रभाव के अनुरूप जिम्मेदारियां नहीं मिलीं। प्रमुख नियुक्तियों में क्षेत्रीय संतुलन के अभाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं का दावा है कि उनकी उपेक्षा की गई है।

यह फेरबदल संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन इसके बजाय, इसने पहले से मौजूद दरारों को और गहरा कर दिया। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा संगठनात्मक विवाद केवल राज्य स्तर तक सीमित रहता, लेकिन पंजाब के मामले में ऐसा नहीं है। यह संकट ऐसे समय सामने आया है, जब भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व पंजाब को अपनी सर्वोच्च राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल कर चुका है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है।

नई दिल्ली में पार्टी की सोच स्पष्ट है। भाजपा का मानना है कि पिछले दो दशकों की तुलना में आज पंजाब की राजनीति कहीं अधिक परिवर्तनशील है। आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता-विरोधी माहौल का सामना कर रही है। कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है और शिरोमणि अकाली दल भाजपा से गठबंधन टूटने और किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव के बाद, अब तक पूरी तरह उबर नहीं पाया है। वर्ष 2020 में गठबंधन टूटने के बाद पहली बार भाजपा को लगता है कि वह पंजाब की राजनीति में स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभर सकती है।

इसी रणनीति के तहत पार्टी ने अपने राजनीतिक समीकरणों में बदलाव शुरू कर दिया है। राज्य अध्यक्ष के रूप में पहले जट सिख नेता केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति की गई। दूसरे जट सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा का दोबारा मौका नहीं दिया गया। सवर्ण नेता तरुण चुघ को मध्य प्रदेश से राज्य सभा भेजा गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी राज्य के नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में अधिक जिम्मेदारियां और केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व देने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य इकाई की राजनीतिक हैसियत बढ़ाना और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरना है।

इसी कारण हाल के महीनों में पंजाब पर केन्द्रीय नेतृत्व का विशेष ध्यान रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है और पिछले महीने जालंधर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर पंजाब संगठन की विस्तृत समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद थे, जिससे स्पष्ट होता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पंजाब के घटनाक्रम पर कितनी गहराई और बारीकी से नजर रख रहा है।

दिल्ली से मिलने वाला संदेश अब बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा अब स्वयं को सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल के साथ दोबारा गठबंधन की प्रतीक्षा करने वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहती। इसके बजाय वह अपने दम पर सत्ता हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है।

यह रणनीति केवल संगठन तक सीमित नहीं है। पिछले एक वर्ष में भाजपा ने पंजाब में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल कर अपना सामाजिक और राजनीतिक आधार लगातार विस्तारित किया है। पर पार्टी को सबसे बड़ी सफलता आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों को अपने साथ लाने के रुप में मिली, जिनमें पार्टी के संगठन और चुनावी रणनीति से जुड़े कई प्रमुख चेहरे शामिल थे। भाजपा इन नेताओं के शामिल होने को केवल अपनी ताकत बढ़ाने के रूप में नहीं, बल्कि अपने प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को भीतर से कमजोर करने की रणनीति के रूप में भी देख रही है।

चाहे जान का खतरा हो, दिसम्बर में बांग्लादेश लौटूंगी- शेख हसीना

नई दिल्ली, 05 अगस्त। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दो वर्षों के अंतराल के बाद बुधवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से वर्चुअल माध्यम से देश और दुनिया को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वे हर हाल में बांग्लादेश लौटेंगी, चाहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए या उनकी जान को खतरा ही क्यों न हो।

■ **दो साल बाद पहली बार शेख हसीना वर्चुअल माध्यम से सार्वजनिक रुप से सामने आईं**

शेख हसीना ने यहां फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया (एफसीसीएसए) में आयोजित वर्चुअल ऑडियो माध्यम से संवाद में लगभग 25 मिनट तक अपना संबोधन दिया। सुरक्षा कारणों से उनका कैमरा बंद रखा गया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों के सवालों के भी जवाब दिए। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश को लोकतंत्र, विकास और धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर वापस लाने के लिए होगी।

भारत की म्यांमार से जमीन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदला-बदली का प्रस्ताव है। यह लगभग 2.8 किलोमीटर की लम्बाई में फैला हुआ है तथा म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र की कबाव घाटी से लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की कि "सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका निर्धारण अभी बाकी है" और उन पर बातचीत जारी है। हालांकि उन्होंने जमीन की अदला-बदली के प्रस्ताव की स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की। भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से लगभग 171 किलोमीटर का हिस्सा अब भी पूरी तरह तय नहीं हुआ है।

मैतेई समुदाय के नागरिक संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (कोकोमी) ने इस संबंध में प्रकाशित रिपोर्टों के बाद केन्द्र और राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता "किसी भी कीमत पर समझौते का विषय नहीं हो सकती।" उसका कहना है कि 1949 में भारत में विलय के बाद मणिपुर अपने ऐतिहासिक भूभाग का बड़ा हिस्सा पहले ही खो चुका है और अब राज्य की सीमा में किसी भी तरह की और कमी स्वीकार नहीं की जाएगी। "कोकोमी" ने कहा कि यदि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया तो वह "मूक दर्शक" बनकर नहीं बैठेगा। संगठन ने यह भी मांग की कि राज्य की सीमा से जुड़ा कोई भी फैसला लोगों की सहमति के बिना न लिया जाए और नई दिल्ली को "आग से खेलने" जैसी गलती करने से बचना चाहिए।

भारत सरकार का मानना है कि सीमा का पूरा निर्धारण हो जाने के बाद ही पूरी सीमा पर बाड़ लगाना संभव हो सकेगा। वर्ष 2024 में केन्द्र सरकार ने पूरी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था (फ्री मूवमेंट रिजीम) समाप्त करने की घोषणा की थी। सरकार का कहना है कि इससे अवैध घुसपैठ, सीमा पार उग्रवादियों की आवाजाही, मादक पदार्थों की तस्करी और पूर्वोत्तर में लंबे समय से चल रहे अन्य अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

इस विवाद की जड़ें औपनिवेशिक काल में हुये सीमा निर्धारण से जुड़ी हैं। प्रथम एंग्लो-बर्मा युद्ध के बाद 1826 की यांडाबो संधि ने दोनों क्षेत्रों की सीमा तय करने की दिशा तय की। इसके बाद 1834 की पेम्बर्टन रेखा के तहत, कबाव घाटी को बर्मा को सौंप दिया गया और इसके बदले मणिपुर को मुआवजा दिया गया। इसके बाद भी कई बार सीमा में बदलाव किए गए, जो 1937 में बर्मा के ब्रिटिश भारत से अलग होने तक जारी रहे। वर्ष 1967 के भारत-बर्मा सीमा समझौते के तहत, सीमा का औपचारिक निर्धारण किया गया, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, तकनीकी समस्याओं और स्थानीय संवेदनशीलताओं के कारण, कई हिस्सों, विशेषकर मणिपुर के कबाव घाटी क्षेत्र, का सीमांकन पूरा नहीं हो सका। इसके बाद ही बनी सरकारों ने इसे किसी नए क्षेत्रीय दावे के बजाय, सीमा-निर्धारण से जुड़ी तकनीकी समस्या माना है।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोर्ट में बढ़ते मामलों के बोझ को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। उन्होंने कहा कि संविधान पीठों के गठन के कारण नियमित मामलों की सुनवाई प्रभावित होती है।

हाल ही में गठित 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े मामलों के चलते अन्य मामलों की सुनवाई में देरी होती है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती है। इस संशोधन के तहत, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ कर 38 की जा रही है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी तथा एक साथ अधिक मामलों की सुनवाई संभव होगी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908